समक्ष जी.सी मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम– *अपीलकर्ता*

बनाम

टी.सी वर्मानी– प्रतिवादी

1975 **की ऑर्डर से प्रथम अपील संख्या 78**

22 मार्च 1984

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (***1948*** का ***XXXIV) - 1966*** के अधिनियम ***44*** और धारा ***40*** द्वारा संशोधित धारा ***2(9) -*** पूर्वव्यापी संचालन देने के लिए संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित कर्मचारी की परिभाषा**,** मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों को उक्त परिभाषा में शामिल किया गया है संशोधन। अधिनियम-संशोधन के काफी बाद निगम द्वारा नियोक्ता के खिलाफ मांग उठाना-नियोक्ता क्या मांग की तारीख से उत्तरदायी है निगम-क्या नियोक्ता को सूचित करने के लिए बाध्य है कि वह अधिनियम के अंतर्गत आता है।

अभिनिर्णित, 1966 के अधिनियम 44 द्वारा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) को पढ़ने से पता चलता है कि 'कर्मचारी' की परिभाषा प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित ऐसे व्यक्तियों तक विस्तारित थी। कारखाने या प्रतिष्ठान या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के लिए कच्चे माल की खरीद, या कारखाने के उत्पादों के वितरण या बिक्री के साथ, और इस तिथि से पहले प्रधान कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को उक्त परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। . इस प्रकार प्रधान कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी 'कर्मचारी' शब्द में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और नियोक्ता अधिनियम के अनुसार मांग के अनुसार योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 2)

अभिनिर्णित, अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निगम को यह कर्तव्य देता हो कि वह फैक्ट्री मालिकों को सूचित करता रहे कि वे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। निगम नियोक्ता का सलाहकार नहीं है और वास्तव में कारखाने के प्रमुख नियोक्ता पर एक कर्तव्य लगाया जाता है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और उस मामले के लिए कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से काट लें और उसे भेज दें। नियोक्ता के अंशदान सहित निगम को। यदि नियोक्ता कर्मचारियों के योगदान में कटौती करने में विफल रहता है, तो निगम में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 40 मुख्य नियोक्ता पर योगदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी डालती है। इस प्रकार, नियोक्ता द्वारा योगदान उस तारीख से किया जाना है जिस दिन कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है, न कि निगम से मांग की तारीख से।

(पैरा 9 और 10)

श्री पी. सी. नारियाला कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, बल्लभगढ़, जिला गुड़गांव के आदेश, दिनांक 30 नवंबर, 1974 से पहली अपील, इस निष्कर्ष के साथ आवेदन का निर्णय करती है कि वादी-कंपनी के प्रधान कार्यालय के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम और योजना 16 दिसंबर, 1969 से प्रभावी है और वादी-कंपनी उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के विशेष योगदान और कर्मचारियों के हिस्से में योगदान करने के लिए व्यवहार्य है।

के.एल. कपूर, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।
प्रतिवादी की ओर से आनंद प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस.पी. जैन, अधिवक्ता।

निर्णय

गोकल चंद मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) यह आदेश 1975 के एफएओ संख्या 78 और 83 का निपटान करेगा क्योंकि ये समान कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली क्रॉस अपील हैं।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (इसके बाद इसे निगम कहा जाएगा) ने टी. सी. विरमानी, वर्क्स मैनेजर के माध्यम से मेसर्स कालकाजी कंप्रेसर वर्क्स, फरीदाबाद के खिलाफ * योगदान के संबंध में एक मांग की, क्योंकि उनका कारखाना प्रावधानों के तहत कवर किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,. 1948 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है)। वर्क्स मैनेजर ने अधिनियम की धारा 75 के तहत एक याचिका दायर कर इस मांग को चुनौती दी कि अधिनियम की धारा 2(9) में निहित कर्मचारी की परिभाषा को अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। 1966 की संख्या 44 28 जनवरी 1968 से प्रभावी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 'कर्मचारी' की परिभाषा को कारखाने या प्रतिष्ठान या किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित ऐसे व्यक्तियों तक बढ़ा दिया गया। उसके लिए कच्चे माल की खरीद, या कारखाने के उत्पादों के वितरण या बिक्री के साथ, और इस तिथि से पहले मुख्य कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था और पहली बार निगम ने जुलाई में एक निर्णय लिया था। 1970, मुख्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को योगदान जमा करने के प्रयोजनों के लिए शामिल करना, न कि उससे पहले। उनका यह भी मामला था कि जुलाई, 1970 के बाद, प्रधान कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के संबंध में योगदान का भुगतान विरोध के तहत किया जा रहा था, हालांकि प्रधान कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का कारखाने से कोई लेना-देना नहीं था क्योंकि कारखाने का अपना प्रशासनिक कार्यालय था। फैक्ट्री परिसर में

जिसका नियंत्रण प्रधान कार्यालय से स्वतंत्र श्री टी. सी. विरमानी द्वारा किया जा रहा था।

(3) निगम ने मामले का विरोध किया और दलील दी कि अधिनियम के तहत दायित्व मांग की तारीख से नहीं है, बल्कि यह 28 जनवरी, 1968 से शुरू हुआ जब 'कर्मचारी' की परिभाषा में उस तारीख से संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सभी संबंधित व्यक्ति कारखाने के उत्पादों की बिक्री को "कर्मचारी" की परिभाषा में शामिल किया गया। चूंकि कारखाने के उत्पादों की संपूर्ण बिक्री का प्रबंधन प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा था, इसलिए, प्रधान कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी "कर्मचारी" की परिभाषा में आते थे, और प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के संबंध में योगदान की उचित मांग की गई थी।

पार्टियों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

1. क्या वर्तमान मुकदमा चलने योग्य है? ओपीपी
2. क्या वादी-फैक्ट्री के प्रधान कार्यालय के कर्मचारी ई.एस.आई. के अंतर्गत कवर नहीं हैं? ओपीपी (आपत्ति जताई गई)
3. क्या प्रतिवादी 28 जनवरी, 1968 के बाद की अवधि के लिए राशि वसूलने का हकदार नहीं है? ओपीपी.
4. क्या प्रतिवादी ब्याज का हकदार नहीं है? ओपीपी,
5. राहत.

(4) साक्ष्य स्वीकार किए जाने के बाद, कर्मचारी बीमा न्यायालय ने दिनांक 30 नवंबर, 1974 के आदेश द्वारा, अंक संख्या 1 के तहत माना कि याचिका सुनवाई योग्य थी; मुद्दा संख्या 2 कारखाने के विरुद्ध तय किया गया था, और मुद्दा संख्या 3 के तहत यह माना गया था कि चूंकि निगम ने 16 दिसंबर, 1969 को एक मांग बनाई थी, केवल उस तारीख तक योगदान का भुगतान किया जाना था और पिछली अवधि के लिए योगदान देय था। मांग नहीं की जा सकी क्योंकि 16 दिसंबर, 1969 से पहले की अवधि के दौरान कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया था। हिंदुस्तान

एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (1) कारखाने की ओर से उद्धृत किया गया था और चूंकि नहीं मुद्दा संख्या 4 पर तर्क आगे बढ़ाया गया, कारखाने के आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और 16 दिसंबर, 1969 से पहले की अवधि की मांग को अवैध माना गया और 16 दिसंबर, 1969 से आगे की अवधि से संबंधित कारखाने के आवेदन को अवैध माना गया। बर्खास्त कर दिया गया. जबकि निगम ने 28 जनवरी, 1968 से अंशदान का दावा करने के लिए 1975 का एफ.ए.ओ. संख्या 78 दायर किया था, फैक्ट्री-एफ.ए.ओ. में आ गई है। 1975 की संख्या 83 में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी अवधि के लिए योगदान की गणना करते समय प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) विद्वान परामर्शदाता द्वारा सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, मेरा मानना है कि निगम की अपील सफल होने योग्य है और फैक्ट्री की अपील में कोई योग्यता नहीं है। इससे पहले कि मैं प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूं, रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्री टी. सी. विरमानी, वर्क्स मैनेजर, फैक्ट्री के गवाह के रूप में उपस्थित हुए, जिनका बयान फ़ाइल के पृष्ठ 143 पर दर्ज किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि के.जी. खोसला एंड कंपनी कालकाजी कंप्रेशर्स का मुख्य कार्यालय है और कारखाने की बैलेंस शीट मुख्य कार्यालय द्वारा बनाई गई थी। हालाँकि, उन्हें यह नहीं पता था कि फैक्ट्री और हेड ऑफिस की बैलेंस शीट एक थी या नहीं। ■ उन्होंने आगे बताया कि तैयार माल कभी हेड ऑफिस तो कभी बाहर भेजा जाता था. वह फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन मुख्य कार्यालय से लेता था।

(6) मेसर्स के.जी. खोसला एंड कंपनी के के.एल. मेहरा पी.डब्लू.5 के रूप में उपस्थित हुए और उनका बयान फ़ाइल के पृष्ठ 143 पर दर्ज किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्य कार्यालय के 80 प्रतिशत कर्मचारी बिक्री विभाग में हैं। यह भी सच है कि फैक्ट्री परिसर में एक प्रशासनिक

कार्यालय है और श्री टी. सी. विरमानी वर्क्स मैनेजर के रूप में प्रशासनिक कार्यालय के प्रभारी हैं!1. वह प्रशासनिक कार्यालय कभी-कभी कारखाने और उसके परिसर की सामग्री की खरीद, उत्पादन और रखरखाव से संबंधित होता है। हालाँकि, कारखाने द्वारा बनाए गए उत्पादों की सभी बिक्री प्रधान कार्यालय में या प्रधान कार्यालय के निर्देशों के तहत की जाती है। बैलेंस शीट मुख्य कार्यालय में तैयार की जाती है और कारखाने के कर्मचारियों का मासिक वेतन भी मुख्य कार्यालय से निकाला जाता है।

एक बार जब फैक्ट्री परिसर में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री मुख्य कार्यालय में विनियमित हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बिक्री मुख्य कार्यालय में कार्यरत सेल्समैन के माध्यम से की जाती है, इस प्रकार मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों को भी 'की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। 28 जनवरी, 1968 को अस्तित्व में आए संशोधन के आधार पर 'कर्मचारी'। तथ्यों पर, कारखाने की ओर से डॉ. आनंद प्रकाश ने जो बड़ा मुद्दा उठाया, वह यह है कि प्रधान कार्यालय में काम करने वाले सेल्समैन को कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए। अंशदान की गणना के प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों के पास कोई योग्यता नहीं है। इस दृष्टिकोण के लिए, मुझे द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बॉम्बे, (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद बनाम श्रीकृष्ण बॉटलर्स (2) मामले में बताए गए निर्णयों से समर्थन मिलता है। पी) लिमिटेड, (3) इंडिया जूट कंपनी लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य, (4) हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली और अन्य, (5) हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कर्मचारी बीमा न्यायालय और अन्य, (6) और रॉयल टॉकीज़। हैदराबाद और अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (7)।

(7) तब निगम की ओर से यह तर्क दिया गया कि: योगदान की मांग कर की मांग है न कि; क्विड, प्रो एयूओ का शुल्क और सिद्धांत लागू नहीं हैं।

इस संबंध में, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के मामले सुप्रा, मेसर्स ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम ई.एस.आई. पर भरोसा किया गया है। कॉर्पोरेशन (8) और शक्ति पाइप्स लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मद्रास, (9)। यह अधिनियम कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक लाभार्थी कानून है और इस उद्देश्य के लिए योगदान एकत्र किया जाता है। निगम द्वारा प्राप्त योगदान कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, गैर रोजगार लाभ, चोटों के लिए मुआवजा, कमाई की हानि आदि जैसे लाभों के भुगतान के लिए उपलब्ध रेडीफंड बन जाता है।

जिस क्षण कोई कर्मचारी, जो अधिनियम के तहत लाभ का हकदार है, दावा करता है तो उसे भुगतान करना होगा। इन तथ्यों पर प्रतिदान के सिद्धांतों का दूर-दूर तक ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता।

(8) मैं एक कदम आगे जाकर कहना चाहूंगा कि भले ही मामले में प्रतिदान का सिद्धांत लागू किया जाता है, योगदान का संग्रह सख्ती से उन सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से होता है जो इसके दायरे में आते हैं। कार्यवाही करना। इसलिए, उन दावों या लाभों के खर्चों को पूरा करने के लिए योगदान देय है जिनके लिए कर्मचारी अधिनियम के तहत हकदार हो सकते हैं। इस प्रकार, अंशदान के भुगतान का कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से सीधा संबंध है। इसलिए, मामले को किसी भी कोण से देखने पर, अंशदान उसी क्षण देय होगा जब कोई कर्मचारी अधिनियम के दायरे में आता है, भले ही निगम मांग तुरंत करता हो या कुछ समय बाद।

(9) मैंने डॉ. आनंद प्रकाश से कहा था कि मान लीजिए कि मुख्य कार्यालय में काम करने वाले एक सेल्समैन की मृत्यु 28 जनवरी, 1968 के बाद और दिसंबर, 1969 से पहले हो गई थी, जब निगम द्वारा मांग की गई थी, तो क्या ऐसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी मुआवजे का दावा नहीं कर सकते? निगम से अधिनियम? इस पर विद्वान अधिवक्ता कोई उत्तर नहीं दे सके।

अधिनियम को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालयों में काम करने वाला सेल्समैन जहां बिक्री या फैक्ट्री उत्पादों का संचालन किया जाता है, ऐसा सेल्समैन 'कर्मचारी' की परिभाषा में आएगा और इसके तहत लाभ का हकदार होगा। अंशदान का भुगतान करने के लिए संबंधित कर्तव्य/दायित्व के साथ कार्य करें।

(10) इसके अलावा, अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निगम को यह कर्तव्य देता हो कि वह फैक्ट्री मालिकों को सूचित करता रहे कि वे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। निगम उनका सलाहकार नहीं है. इसके विपरीत, जब यह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है तो कारखाने के प्रमुख नियोक्ता पर यह कर्तव्य लगाया जाता है कि वह कर्मचारियों के योगदान को उनके वेतन से काट ले और उसे नियोक्ता के योगदान के साथ निगम को भेज दे। यदि नियोक्ता कर्मचारियों के योगदान में कटौती करने में विफल रहता है, तो निगम पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 40 मुख्य नियोक्ता पर योगदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी डालती है। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, मुझे साउदर्न रोडवेज (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (10) और प्रेम सुख और अन्य बनाम प्रबंधक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य, (11) से समर्थन मिला। इसलिए, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती कर रही थी कि निगम दिसंबर, 1969 से पहले योगदान की मांग करने का हकदार नहीं था, क्योंकि उस तारीख से पहले कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया था।

(11) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, 1975 के एफएओ नंबर 78 की अनुमति दी जाती है और नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश को संशोधित किया जाता है और यह माना जाता है कि निगम द्वारा किए गए योगदान की पूरी मांग उचित थी और कारखाने द्वारा धारा 75 के तहत दायर किया गया आवेदन अधिनियम में कोई योग्यता नहीं थी। परिणामस्वरूप, 1975 की एफएओ संख्या 83 और अधिनियम की धारा 75 के तहत कारखाने

द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया जाता है। निगम को इन दोनों अपीलों में लागत होगी जो 500 रुपये में निर्धारित की गई है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा